आयोग का दौरा

सरसों का समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए नए फार्मूले पर विचार

तेल की मात्रा से तय होगा समर्थन मूल्य!

भरतपुर में सरसों के समर्थन मूल्य निर्धारण पर चर्चा करते आयोग के अध्यक्ष व व्यापारी।

मिलावट ने किया कबाड़ा

सरसों तेल उत्पादक व्यापारियों का कहना था कि मिलावटी तेल बाजार में धडल्ले से बिक रहा है। यदि ऐसे हालात लम्बे समय रहे तो देश में सरसों तेल उद्योग समाप्त हो जाएगा। समर्थन मूल्य चाहे कितना भी ज्यादा हो जाए, मूल चुनौतियों की ओर भी देखना जरुरी है। चर्चा के दौरान आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव ने कहा कि तेल के प्रतिशत के आधार पर समर्थन मूल्य निर्धारित करने की दिशा में मंथन चल रहा है। अभी कुछ तय नहीं है। निर्णय ऐसा हो जिससे किसान और व्यापारी दोनों का लाभ हो।

इन बिन्दुओं पर भी ली जानकारी

- किसानों को सरसों का भुगतान कैसे होता है?
- भुगतान के लिए प्रतिशत का फंडा क्या है?
- तेल की मात्रा निश्चित करने के लिए लैब की क्या व्यवस्थाएं है?
- क्या सैंपल जांच के लिए भुगतान किसान को देना होता है?
- तेल उद्योग संचालन पर क्या लागत आती है?

भरतपुर. सरसों के लिए समर्थन मूल्य तेल की मात्रा के आधार पर हो सकता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अध्यक्ष डॉ. अशोक बिशानदास एवं सदस्य सचिव डॉ. शैलजा शर्मा ने शुक्रवार को भरतपुर यात्रा के दौरान वैज्ञानिकों, कृषि विभाग के अधिकारियों, किसानों एवं तेल उत्पादक व्यापारियों से चर्चा कर इस मुद्दे पर फीडबैक लिया।

किसान बोले, खेती नहीं फायदे का सौदा

सरसों अनुसंधान निदेशालय में चर्चा के दौरान किसानों ने आयोग के पदाधिकारियों को बताया कि वर्तमान में खेती का लागत काफी बढ़ चुकी है। डीजल, खाद-बीच महंगे हैं। मौसम की मार भी ज्यादा पड़ रही है। खेती की लागत काफी बढ़ चुकी है, ऐसे में खेती अब फायदे का सौदा नहीं रहा। जो भी नीति बनाए किसानों के हितों का ध्यान रखा जाए।

वैज्ञानिकों ने कहा, किसान का मन समझें

चर्चा के दौरान सरसों अनुसंधान निदेशालय के निदेशक डॉ. धीरज सिंह ने उदाहरण दिया कि बाजार में ग्वार का मूल्य ऊंचा होने के कारण किसानों का रुझान ग्वार की तरफ बढ़ा। सरसों उत्पादक किसानों को यदि फसल से लाभ नहीं मिलेगा तो वे इसे क्यूं बोएंगे? उनका सुझाव कि समर्थन मूल्य इतना होना चाहिए कि किसान को सरसों बोनालाभकारी लगे।

अधिकारियों, व्यापारियों ने भी बताए तथ्य

इस मौके पर सरसों अनुसंधान निदेशालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अशोक कुमार शर्मा, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक रामलाल पुरोहित, उप निदेशक देशराज सिंह, आत्मा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉ. योगेश शर्मा, कृषि उपज मंडी सचिव मोहनलाल, भरतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्डस्ट्रीज के महामंत्री अनुराग गर्ग, तेल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष रामनाथ, देवेन्द्र कुमार, गोविंद गुप्ता मौजूद थे।

राजस्थान पत्रिका 19 जुलाई 2014

सरसों के समर्थन मूल्य पर चर्चा

भास्कर न्यूज. भरतपुर

भारत सरकार का प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को भरतपुर चैंबर आफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज नई मंडी चैंबर भवन पहुंचा, जहां चैयरमैन सहित कृषि विशेषज्ञों ने सरसों, खल, सरसों तेल पर प्राइस निर्धारित करने, किसानों को समर्थन मूल्य आदि पर चैंबर पदाधिकारियों एवं तेल उद्यमियों से विचार-विमर्श किया।

प्रतिनिधि मंडल ने यह जानने की कोशिश की सरसों का समर्थन मूल्य किस आधार पर तय निर्धारित किया जाए। इस अवसर पर तेल उद्यमियों, लैब टेक्नीशियन आदि ने विचार रखे। भारत सरकार के चेयरमैन कमीशन आफ कृषि कोस्ट एण्ड प्राइस विभाग डॉ. अशोक विशनदास ने सरसों लैब, तेल निकालने, कीमत आंकने के बारे में भारत सरकार की नीतियों की जानकारी दी तथा बताया कि इससे हमें सरसों पर निर्धारित मूल्य निकालने का सही आंकलन मिल पाएगा।

भरतपुर. चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में उपस्थित संभागी।

इस अवसर पर तेल मिल एसोसिएशन अध्यक्ष रामनाथ, देवेन्द्र कुमार, लैब टैक्निनिशियन गोविंद गुप्ता, तेल उद्यमी रविन्द्र गोयल, प्रमोद गुप्ता, प्रदीप बंसल, राजेन्द्र गोयल, राजीव मित्तल, मदनमोहन गर्ग आदि ने विचार रखे। सदस्य सचिव डॉ. शैलजा शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अशोक शर्मा आदि ने सरसों का समर्थन मूल्य तय करने आदि की जानकारी दी। संचालन अनुराग गर्ग ने किया व आभार गोविंद गुप्ता ने जताया।

दैनिक भास्कर 19 जुलाई 2014